बड़े औद्योगिक घरानों का रुख अब यूपी की ओर

21 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव इन्वेस्टर्स समिट से पहले ही मिले

7.2 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेंगी दिग्गज विदेशी कंपनियां

निवेश आकर्षित करने के मामले में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एक नया मील का पत्थर स्थापित करने जा रही है। 10 फरवरी से 12 फरवरी तक आयोजित होने वाले उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले ही 21 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। इन निवेश प्रस्तावों में से 7.2 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव विदेश में हुए रोड शो के दौरान दिग्गज वैश्विक कंपनियों से मिले हैं। देशी-विदेशी उद्यमियों द्वारा निवेश से प्रदेश में बड़ी संख्या में उत्पादन और सेवा आधारित उद्यमों की स्थापना होगी। साथ ही पहले से स्थापित उद्यमों की क्षमता का विस्तार होगा। इससे प्रदेश में बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार के नये अवसरों का सृजन होगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य रखा है, उसमें 20 प्रतिशत योगदान का संकल्प उत्तर प्रदेश ने लिया है। उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने युद्धस्तर पर कार्य शुरू किया। नये-नये कदम उठाये। लॉजिस्टिक्स विकास को गति देकर प्रदेश को उत्पादन का हब बनाने के लिए निवेशकों और उद्यमियों को सभी जरूरी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि पिछले लगभग छह वर्षों में 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश प्रदेश में हुआ है। आज देश-दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर उत्साहित हैं।

उत्तर प्रदेश आज डाटा सेंटर का हब बन रहा है। प्रदेश के पहले डाटा सेंटर का लोकार्पण ग्रेटर नोएडा में किया जा चुका है। देश की पहली डिस्प्ले यूनिट प्रदेश में लग गयी है, जिसमें उत्पादन प्रारम्भ हो गया है। आईटी और आई.टी.ई.एस. समेत अनेक सेक्टरों में निवेश की सम्भावनाओं के नये द्वार खुले हैं। 10-12 फरवरी तक होने वाले यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए दुनिया भर के निवेशकों को आमंत्रित करने विदेश गयीं टीमों के जरिये आईटी और आई.टी.ई.एस. सेक्टर में भारी निवेश के कई प्रस्ताव मिले।

निवेश और रोजगार सृजन पर जोर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुम्बई में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के संबंध में आयोजित रोड शो के दौरान अपनी टीम के सदस्यों के साथ

उत्तर प्रदेश के अंदर इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है। हमारे पास अच्छी कनेक्टिविटी है। आज प्रदेश का प्रत्येक कोना रेल, अच्छे हाइवे और एयर कनेक्टिविटी की सुविधा से जुड़ा हुआ है। पिछले छह वर्षों में नियोजित प्रयासों के साथ, यूपी देश में औद्योगिक निवेश के लिए सबसे अच्छा गंतव्य बनकर उभरा है। उत्तर प्रदेश ओडीओपी से वैश्विक स्तर पर अलग पहचान विकसित कर रहा है। उत्तर प्रदेश एक उभरती आर्थिक शक्ति के रूप में विकसित हो रहा है।

\- योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री

योगी सरकार ने पिछले कार्यकाल से ही कारोबारी सुगमता के लिए, स्वतः स्वीकृति, भूमि उपयोग और विकास शुल्क में छूट, स्टाम्प शुल्क और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट के साथ कौशल विकास सब्सिडी देने समेत ढेरों कदम उठाये हैं। इन कदमों ने उत्तर प्रदेश को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में चौदहवें से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया। जबकि 2021 के सर्वे के मुताबिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यह किसी भी राज्य के लिए सबसे ऊंची छलांग है।

बढ़ती कारोबारी सुगमता का ही परिणाम है कि बड़े-बड़े कारोबारी और निवेशक उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में सहभागी बनने के लिए आगे आ रहे हैं। गूगल, अडोबी, सैमसंग, टाटा, अडानी, आईटीसी और जैकेट्स ग्रुप जैसे दिग्गज कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आगे आ रही हैं।

विशेषताओं ने बनाया निवेश का पसंदीदा गंतव्य

उत्तर प्रदेश की विशेषताएं इसे निवेश के लिए सर्वोत्तम गंतव्य बनाती हैं। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक स्थायित्व के साथ गुड गवर्नेंस वाली सरकार है। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध यूपी गुड गवर्नेंस, अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरेंस, सबसे बड़े उपभोक्ता बाजार, सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र, निवेश फ्रेंडली नीतियों के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य है। यूपी हर लिहाज से निवेश के लिए सर्वोत्तम जगह है। उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प के अनुरूप उत्तर प्रदेश भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को गति देने के लिए तैयार है।

दूसरे राज्यों से आवागमन और माल ढुलाई की सुलभता

दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का 8.5 प्रतिशत और अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का 57 प्रतिशत हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। दोनों ही कॉरिडोर के आसपास 150 से 200 किलोमीटर के क्षेत्रफल में औद्योगिक केंद्र भी स्थापित होंगे। इन केंद्रों को स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार अनुदान राशि देगी। औद्योगिक केंद्रों में स्टोरेज, प्लांट, लॉजिस्टिक हब व इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर निर्मित किये जाएंगे। इसके निर्माण के लिए भूमि राज्य सरकार द्वारा और आवश्यकता ढांचा अथवा सुविधाएं केंद्र सरकार द्वारा दी जाएंगी।

इन दोनों कॉरिडोर का जंक्शन ग्रेटर नोएडा में है। इससे यह उत्तरी भारत में सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब बन जाएगा। ग्रेटर नोएडा के जेवर में भारत के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास किया जा रहा है। इससे एक ओर जहां देश-विदेश से लोगों के आवागमन में सुविधा और समय की बचत होगी, वहीं माल ढुलाई की सुलभता बढ़ जाएगी। इस पहलू ने भी निवेशकों और उद्यमियों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित किया है।

उत्तर प्रदेश आज निवेश का केंद्र बन रहा है। बड़ी-बड़ी कंपनियां आज यूपी आने के लिए उत्सुक हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं, रोजगार के नये अवसर तैयार हो रहे हैं। यूपी और यूपी के लोगों ने देश के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। यूपी में चल रहे हाईवे, एक्सप्रेसवे और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और डिफेंस कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, ये उसका जीता-जागता उदाहरण है।

\- नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

देश में हुए रोड शो में प्राप्त निवेश प्रस्ताव

मुंबई	5,00,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव
दिल्ली	2,75,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव
अहमदाबाद	41,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव
हैदराबाद	25,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव
बेंगलुरु	25,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव
चंडीगढ़	11,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव
चेन्नई	9,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव
कोलकाता	7,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव

बोले दिग्गज

हर्ष अग्रवाल, सीएफओ, एडवांस ट्राइडेंट वेंचर प्राइवेट लिमिटेड

योगी जी डायनमिक मुख्यमंत्री हैं। जिस तरह से वह यूपी में इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं, वह अपने आप में एक मॉडल है। उत्तर प्रदेश में आज कानून-व्यवस्था अच्छी हुई है। अपराध में कमी आई है। कुशल श्रमिकों की भरमार है। इससे उद्योग लगाने का एक अच्छा माहौल बना है। ये सब योगी जी की कार्यकुशलता की वजह से हो पाया है। आज हमने उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए एमओयू किया है। हम यूपी में 10 से 15 एकड़ में प्लांट लगाएंगे। हम सीएम योगी के संकल्प को सिद्धि तक ले जाएंगे।

रमन सिंगला, निदेशक कॉस्मिक टेक्नोलॉजीज इंडिया

पिछले 5-6 वर्षों में यूपी में काफी कार्य हुआ है। हवाई, सड़क और जल कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास से उद्यम का माहौल बना है। योगी जी विजनरी और प्रगतिशील मुख्यमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में यूपी भारत का ग्रोथ इंजन बनेगा और अपनी अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर का आकार देने में सफल होगा।

दीप नारायण शर्मा, एमडी बायोवेट लाइफसाइंस

सीएम योगी आदित्यनाथ के अथक प्रयासों से आज यूपी देश का सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर बढ़ रहा है। सिंगल विंडो सिस्टम और फास्ट ट्रैक अप्रूवल से यूपी में उद्यम लगाना आसान हो गया है। हम उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। अभी हिमाचल में हमारे प्लांट हैं। जिस तरह से योगी जी निवेशकों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उससे हमारे मन में भी यूपी में निवेश करने और अपने समाज एवं प्रदेश के लिए कुछ करने की प्रबल इच्छा जगी। इसके लिए हमने फार्मुलेशन और एपीआई प्लांट में निवेश के लिए दो एमओयू पर हस्ताक्षर किये हैं।

बुंदेलखंड को मिले 1,11,611 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष फोकस वाले बुंदेलखंड के लिए उद्योग जगत ने अपनी तिजोरी खोल दी है। दशकों से पिछड़े क्षेत्र के रूप में पहचाने जाने वाले बुंदेलखंड में निवेश को लेकर आए प्रस्तावों ने नया कीर्तिमान रच दिया है। प्रदेश के जिलों में स्थानीय स्तर पर हो रहे इन्वेस्टर्स समिट में झांसी ने अब तक सभी जिलों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

झांसी में हुए इन्वेस्टर्स समिट में 1,11,611 करोड़ रुपये के 146 से अधिक प्रस्ताव मिले, जिनमें से 65 हजार करोड़ रुपये के लिए एमओयू भी हो चुके हैं। इससे लगभग 56 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। इनमें ऊर्जा के क्षेत्र में सर्वाधिक 50 हजार करोड़ रुपये का एमओयू हुआ है।

झांसी जिले में पर्यटन, फार्मा, टेक्सटाइल और एमएसएमई क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में निवेशकों ने दिलचस्पी दिखाई है। झांसी को डिफेंस कॉरिडोर का भी फायदा मिलेगा। रक्षा संबंधी जो कल-पुर्जे अभी तक बाहर से आते थे, वे अब झांसी के डिफेंस कॉरिडोर में बनेंगे। इससे बुंदेलखंड के लोगों को लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

2 लाख करोड़ रुपये का निवेश आयेगा सौर ऊर्जा क्षेत्र में

निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा और संबंधित क्षेत्रों में करीब दो लाख करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। राज्य सरकार ने 'उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022' को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद राज्य में 2027 तक 22 गीगावाट की हरित ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करना है। इस नीति के तहत निवेशक सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए दो लाख करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता पहले ही जता चुके हैं।

इससे कृषि क्षेत्रों की परियोजनाओं के साथ ही रूफटॉप सौर परियोजनाओं से राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा सरकार का लक्ष्य अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क और मॉडल सोलर सिटी आदि का विकास करना भी है। राज्य सरकार विभिन्न सब्सिडी के अलावा अन्य तरीकों से भी सौर ऊर्जा उत्पादन और भंडारण के लिए प्रोत्साहन दे रही है।

एमएसएमई पार्क के लिए 1 प्रतिशत ब्याज पर ऋण

योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को एक और बड़ी राहत प्रदान की है। यूपी कैबिनेट ने निजी औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए प्रमोशन ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपमेंट आफ एमएसएमई योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 10 से 50 एकड़ भूमि पर निजी औद्योगिक पार्क स्थापित करने पर उद्यमियों को मात्र 1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ऋण दिया जाएगा। इसके लिए जमीन खरीदने पर स्टांप ड्यूटी में शत-प्रतिशत छूट भी मिलेगी। वहीं, निजी औद्योगिक पार्क में एमएसएमई यूनिट स्थापित करने के लिए भूखंड खरीदने पर भी स्टांप ड्यूटी में पूरी छूट मिलेगी।

निजी औद्योगिक पार्कों में भूखंडों के आवंटन, संचालन व मूलभूत आवश्यक सुविधाओं के रखरखाव का पूरा दायित्व निजी विकासकर्ता का होगा। विकासकर्ता की ओर से क्लस्टर पर आधारित औद्योगिक पार्कों के विकास से सम्बन्धित प्रस्तावों की जांचकर प्रदान की जाएगी। उनकी ओर से विकसित किये गये औद्योगिक पार्कों में न्यूनतम प्रति एकड़ 1 इकाई को भूखंड आवंटित करना अनिवार्य होगा तथा कुल विकसित भूमि में से 75 प्रतिशत भूखंड एमएसएमई इकाइयों के लिए आरक्षित रखा जाएगा।

2,500 करोड़ रुपये का रिवाल्विंग फंड : निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 2,500 करोड़ रुपये का रिवाल्विंग फंड बनाया जाएगा।

यूपी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2022 : खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2022 को भी मंजूरी दे दी है। इस नीति में 12.5 एकड़ से अधिक भूमि खरीदने की अनुमति, गैर कृषि उपयोग घोषणा के लिए शुल्क से छूट देने की व्यवस्था की गयी है।

यूपी उद्योगों के लिए सर्वोत्तम गंतव्य

योगी सरकार में बेहतर कानून-व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन और वेयरहाउसिंग व लॉजिस्टिक की बेहतर सुविधा होने से उत्तर प्रदेश उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सर्वोत्तम गंतव्य साबित हो रहा है।

\- महेश गुप्ता, चेयरमैन, केंट आरओ

कानपुर के पास में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर में उद्यमियों को अधिक से अधिक भूमि उपलब्ध करानी चाहिए। यहां आर्टिलरी फैक्ट्रियां हैं और यह डिफेंस का हब है। कानपुर डिफेंस के और फैक्ट्रियां लगेंगी। लेकिन इन्वेस्टर्स समिट यूपी के लिए बड़ी उपलब्धि है।

\- मनोज गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष, फिक्की

राज्यों के आखिरी रोड शो में भी यूपी को लेकर उत्साहित दिखे निवेशक

चंडीगढ़ में हुए 11 हजार करोड़ रुपये के एमओयू

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 के लिए चंडीगढ़ में 27 जनवरी को आयोजित अंतिम रोड शो में यूपी में निवेश के लिए 11 हजार करोड़ रुपये के 29 एमओयू किए गए हैं। इस रोड शो के जरिये से 21 हजार से अधिक प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए हुए रोड शो के आखिरी कड़ी में चंडीगढ़ में निवेशकों ने खासा उत्साह दिखाया। रोड शो में बिजनेस टु गवर्नमेंट मीटिंग में एशियन सीमेंट्स लिमिटेड की ओर से उत्तर प्रदेश में सीमेंट प्लांट लगाने का ऐलान किया गया, जबकि बायोवेट लाइफसाइंस प्राइवेट लिमिटेड ने यूपी में फार्मुलेशन और एपीआई प्लांट लगाने के लिए दो समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये हैं।

रोड शो में शामिल हुए निवेशकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संकल्प की सिद्धि तक पहुंचाने के प्रति प्रतिबद्धता जताई। टीम योगी ने निवेशकों को बताया कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा उपभोक्ता वाला राज्य है। यहां पर बड़ी संख्या में युवा एवं कुशल श्रम शक्ति की उपलब्धता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हमारा राज्य नये भारत का नया उत्तर प्रदेश बनकर उभरा है। प्रदेश में बेहतर हुई कनेक्टिविटी पर फोकस करते हुए उन्हें बताया गया कि एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट के विकास से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। पूर्व के किसी भी दौरे में उद्यम लगाना चाहें तो उद्यमियों को आने-जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। यूपी आज अपराधमुक्त, भयमुक्त और विकासयुक्त उत्तर प्रदेश है।

टॉप पांच निवेशक

कंपनी	निवेश प्रस्ताव (करोड़ रुपये में)
यूनिक एनर्जीन प्रा. लि.	1100
स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेज प्रा. लि.	1000
अमर्टेक्स इंडस्ट्री	1000
स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेज प्रा. लि.	1000
माधव केआरजी प्रा. लि.	700

जिलास्तरीय रोड शो

जनपद	निवेश प्रस्ताव
झांसी	1,11,611 करोड़ रुपये
गाजियाबाद	92,000 करोड़ रुपये
लखनऊ	76,000 करोड़ रुपये
कानपुर	70,000 करोड़ रुपये
वाराणसी	48074 करोड़ रुपये
प्रयागराज	33,000 करोड़ रुपये
सीतापुर	26,000 करोड़ रुपये
हापुड़	23,000 करोड़ रुपये
बरेली	14,170 करोड़ रुपये
अलीगढ़	13,422 करोड़ रुपये
चित्रकूट	11,488 करोड़ रुपये
गोण्डा	3,100 करोड़ रुपये
बस्ती	1,850 करोड़ रुपये
बांदा	1,700 करोड़ रुपये
महराजगंज	1674 करोड़ रुपये
संतकबीर नगर	1502 करोड़ रुपये
कुशीनगर	1,305 करोड़ रुपये
सिद्धार्थनगर	565 करोड़ रुपये
बाराबंकी	500 करोड़ रुपये